

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 02 जनवरी 2025, समय 1305 (5 मिनट))

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों को समृद्ध बनाने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश को अपने किसानों पर गर्व है जो कड़ी मेहनत करके पूरे देश का पेट भरते हैं।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने नया साल किसानों को समर्पित किया है। कल नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए तीन बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित पुनर्गठित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने तथा डी.ए.पी उर्वरकों पर अतिरिक्त सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी दी है। श्री चौहान ने कहा कि 2024-25 में भारत के कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में साढ़े तीन से 4 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय ने गैर-बासमती चावल के व्यापार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत भारत इंडोनेशिया को दस लाख टन गैर-बासमती चावल का निर्यात करेगा।

हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने आगामी बजट के लिए पशुपालकों के हित में ठोस कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया है। वह कल पशुपालन विभाग के अधिकारियों से बजट पूर्व चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को सभी शहरों को लावारिस मवेशियों से मुक्त करने और उन्हें गोशालाओं में भेजने की

हिदायत भी की। उन्होंने इन पशुओं के पुनर्वास और समस्या के समाधान के लिए जियो-टैगिंग का उपयोग करने और अधिक गौशालाओं के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने को कहा। पशुपालन मंत्री ने पशुधन नस्ल सुधार और हरियाणा की स्थानीय नस्लों, विशेषकर हरियाणा गाय और मुरा भैंस को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। श्री राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हरियाणा और मुरा जैसी स्वदेशी नस्लों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष मवेशी प्रजनन केंद्र, उन्नत पशु चिकित्सा क्लिनिक और मेगा गोशालाओं की स्थापना की योजना भी तैयार की जाए। इसके अलावा, मंत्री ने अधिकारियों को पशुधन बीमा योजनाओं में अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना बनाने को भी कहा।

हरियाणा के दादरी जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि के चलते करीब 13 हजार एकड़ फसल प्रभावित हुई है। कृषि विभाग द्वारा बनाई रिपोर्ट में ओलावृष्टि के कारण दादरी जिले के 38 गांवों की करीब 13 हजार एकड़ में फसलों में खासा नुकसान हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारी चंद्रभान श्योराण ने बताया कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के लिए सरकार द्वारा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है। किसान 20 जनवरी तक आधार कार्ड और जमीनी दस्तावेजों से पोर्टल पर खराबे के दावे अपलोड कर सकते हैं। ताकि फसलों के खराबे की क्षतिपूर्ति की जा सके। कृषि विभाग ने भी प्रभावित किसानों को पोर्टल पर दावे अपलोड करने का आह्वान किया है।